

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन

ज्योत्सना यादव

शोधार्थी,

एलएनएमयू दरभंगा बिहार

सारांश :- महिलाओं को शिक्षित होने से समाज में होने वाली बुराइयों जैसे— दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न एवम पोषण से निपटारा आदि को दूर किया जा सकता है । महिलाओं को शिक्षा देना उतना ही आवश्यक है, जितना की ऑक्सीजन लेना । महिलाएं शिक्षित होगी तो अपने घर के साथ— साथ समाज का भी विकास करने में मदद करेंगी । महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सरकार भी अनेक योजनाएं बना रही है तथा उसे पर कार्य कर रही है। कुमारी, (2017). महिलाओं के विकास में कौशल की भूमिका में पाया है कि महिलाएं शिक्षा एवं कौशल के माध्यम से रोजगार आर्थिक स्थिति और खान—पान आदि की व्यवस्था मजबूत होता है । शोध क्षेत्र एवं प्रविधि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गौर ब्लाक में 3 से 5 वर्ष के बच्चों के 200 शिक्षित एवं अशिक्षित मां का डाटा प्राथमिक विधि से साक्षात्कार प्रश्नावली सर्वे एवं सेकेंडरी विधि से बुक पत्र पत्रिका आदि से एकत्र किया गया। शोध निष्कर्ष में पाया गया कि जो महिलाएं शिक्षित एवं जागरूक थी, वे अपने परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समाधान करती हैं। संतुलित आहार से बच्चों एवं परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य की देखभाल भी उचित प्रकार से करती हैं ।

की वर्ड — महिला, शिक्षा, विकास, ग्रामीण

प्रस्तावना :-ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षित महिलाओं के कारण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है । शिक्षित महिलाएं न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनती हैं, शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है, और वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, और आस पड़ोस को भी जागरूक करती हैं । महिलाओं का शिक्षित होने के कारण तमाम कुरीतियां, रूढ़िवादी विचारों आदि के खिलाफ आवाज उठाने और समाज में परिवर्तन लाने में भी योगदान करती हैं । वर्तमान समय में महिलाएं आधुनिकरण के प्रभाव से वंचित नहीं हैं, वह घर से बाहर निकल कर कार्य करने लगी हैं, अब वह चार दिवारी में रहकर जीवन जीने में विवश नहीं है, महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई व रहन—सहन आधुनिक बना रही है, इस आधुनिक युग में महिलाएं शिक्षित एवं जागरूक होकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं । वर्तमान समय में ऑनलाइन मोड में शिक्षा का बहुत योगदान रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किशोरियों को गांव से बाहर न जाने के कारण पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न होता था, लेकिन अब ऑनलाइन मोड से शिक्षा बहुत हितकारी साबित हो रहा है । सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से भी जागरूकता देखी जा रही है ,जो महिला शिक्षित है, वह गांव की सरपंच, आशा, आंगनबाड़ी, टीचर, एन एम आदि महिलाएं गांव में भी कार्यरत हैं। गांव में भी जिनके माता—पिता अशिक्षित है, वह भी देखकर अपने बच्चों को बाहर भेज कर उच्च शिक्षा जैसे बीएड, नर्सिंग, बीटीसी आदि प्राप्त कर रहे हैं । शिक्षित मां अपने परिवार और बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल उत्तम तरीके से करती हैं, और जिस बच्चों की मां शिक्षित है, उनके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक था, और जिन बच्चों की मां अशिक्षित थी उन बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वे बच्चे अधिकतर लंबाई या वजन मे कमी और बदलते मौसम में बार—बार बीमार भी पड़ते हैं, और जिन बच्चों की मां शिक्षित थी, पर जागरूक नहीं थी, उन बच्चों के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखा गया है। गरीबी चक्र तोड़ने के लिए शिक्षा एक मात्र साधन है, शिक्षा मनुष्य के विकास में सहायता करता है, हम शिक्षा के माध्यम से न केवल ज्ञान कौशल और कई प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि इसके साथ—साथ शिक्षा मनुष्य के समग्र विकास में मदद करती है, क्योंकि हम शिक्षा के माध्यम से ज्ञान और जीवन में काम आने वाले नैतिक मूल्य जैसे प्रेम भाईचारा शांति अहिंसा और सामाजिक परंपराओं के बारे में सीखते हैं ।

भारत सरकार द्वारा चलाई गई महिलाओं के लिए योजनाएं :-

ये योजना महिलाओं को शिक्षा एवं जागरूक करने के लिए चलाई गई हैं। –

प्रधानमंत्री बंदना योजना :- प्रधानमंत्री मातृ (पी एम एम वी वाई) के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माता को ₹5000 की नगद राशि दी जाती है, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आती है, इस योजना का मकसद मां और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना।

पीएमएमबीवाई के तहत मिलने वाली रकम की जानकारी :- पहले बच्चे के लिए ₹5000 की रकम दो किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त ₹3000 रुपए बच्चा जन्म के पहले और जांच के बाद दी जाती है, दूसरी किस्त ₹2000 बच्चे जन्म और 14 सप्ताह के सार्वभौमिक टीकाकरण के बाद दी जाती है। दूसरा बच्चा यदि लड़की है, तो ₹6000 एक ही किस्त में दिए जाते हैं।

स्टैंड अप इंडिया योजना – स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों को 81प्रषित बैंक उपलब्ध कराती है, ताकि वह ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित कर सके। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य उत्पादों और सेवाओं का विकास और नवाचार करना तथा भारत में रोजगार दर को बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :- उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना 1 में 2016 को शुरू की गई है इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है, इस योजना को लागू करने से वनों की कटाई एवं वायु प्रदूषण को कम करने में भी सहायता प्राप्त होगी, तथा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विकार में भी लाभ प्राप्त होगा।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना :- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में सम्मिलित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ,पक्षपात लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा का सुनिश्चित करना। बालिकाओं को शोषण से बचाना। शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना। महिलाओं को जागरूक करना और कल्याणकारी सेवाएं वितरित करने में सुधार करना आदि।

फ्री सिलाई मशीन योजना :- इस योजना के तहत सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि महिलाएं घर बैठे सिलाई का काम कर सकें, और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें एवं आत्मनिर्भर भी बन सकें, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में 50,000 से अधिक गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना का शुभारंभ किया गया है।

सुकन्या समृद्धि योजना :- यह भारत सरकार की एक बचत योजना है। इस योजना से लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अभिभावक अपनी बेटी के नाम पर खाता किसी डाकघर या बैंक में खोल सकते हैं, इसमें बच्ची की आयु 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, खाता खोलने के लिए न्यूनतम 250 रुपए जमा करने होते हैं, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक जमा किया जा सकता है, अगर किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो मात्रा जमा नहीं किया जाता है, तो खाता चूक के तौर पर माना जाएगा, ब्याज दर, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक तिमाही आधार पर तय की जाती है। अर्जित ब्याज आय कर अधिनियम के तहत टैक्स फ्री है, बालिका की उम्र 18 साल होने या दसवीं कक्षा पास करने के बाद खाते से पैसा निकले जा सकते हैं।

मुद्रा लोन योजना :- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे भारत सरकार द्वारा सूचना और लघु उद्योगों की को ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया एक ऐसी योजना है, जो गैर – कृषि लघु उद्योगों को 20 लाख तक का लक्ष्य प्रदान करती है।

महिला शक्ति योजना :- यह योजना महिलाओं के विकास एवं संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण, संस्कृत सशक्तिकरण, और आर्थिक सशक्तिकरण, से संबंधित एकीकृत कार्य करना है। इसके साथ ही महिलाओं से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण भंडारण आदि। सभी

स्तर पर महिलाओं को आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाना इस योजना से महिला उद्यमी अपना खुद नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाएं :-

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना :- उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की है, जो जन्म से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए लाभ प्रदान करती है, इस योजना का उद्देश्य— बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को सुधार करना, सामान लिंगानुपात स्थापित करना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना।

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना :- उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष नामक एक योजना है, जो विधवाओं और दहेज से संबंधित मुद्दों से प्रभावित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, इसका लाभ महिलाओं को ही मिलता है।

181 महिला हेल्पलाइन नंबर :- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए 181 महिला हेल्पलाइन नंबर एक महत्वपूर्ण सेवा है, जो 24 घंटे उपलब्ध है, और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तत्काल मदद और जानकारी प्रदान करती है। पुलिस, अस्पताल, एंबुलेंस, और अन्य आवश्यक सेवाओं से संपर्क स्थापित करने में मदद करती है।

महिला शक्ति केंद्र योजना :- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला शक्ति केंद्र योजना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए शुरू की गई है, जिसमें जिला स्तरीय महिला शक्ति केंद्र (डीएलसीडब्ल्यू) का गठन किया जाता है, तथा ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य ,और पोषण के अवसरों के साथ सशक्त बनाया जाता है।

वृद्ध महिला आश्रम :- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्ध आश्रमों का संचालन करती है, जिनमें मुफ्त आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

वन स्टाफ केंद्र योजना :- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन स्टाफ केंद्र योजना की शुरुआत 1अप्रैल 2015 को की गई है। यह योजना महिला और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए है, इस योजना को सखी के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है।

हाउ फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन योजना :- यह केंद्र एवं राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलता है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना :- इस योजना के तहत अनाथ बच्चों की बाल्य देखभाल संस्थानों में आवासित किया जाता है, और बालिकाओं को शादी योग्य होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

शोध समीक्षा :-

गांधी.(1930), यंग इंडिया पत्रिका में लाखों महिलाएं यह नहीं जानती की बेरोजगारी क्या है, उन्हें आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच प्रदान करें और महिलाओं के बीच एक जुटता को बढ़ावा देने से स्वास्थ्य पोषण एवम लैंगिक समानता के प्रति जागरूक होंगी। प्रीति. (2021), महिला संविधान में शिक्षा की भूमिका जनरल में शिक्षा ही महिला संविधान के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है, शिक्षा के माध्यम से महिलाएं स्वयं निर्भर स्वतंत्र जागरूक हो रही है, जो हर समाज में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। वाजपेई,(2023), ग्रामीण भारत के रूपरेखा बदलती ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा से महिलाओं में प्रादुर्भाव हो रहा है। कुमारी,(2017), महिलाओं के विकास में कौशल की भूमिका में पाया कि महिलाएं शिक्षा एवं कौशल के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रही हैं, और वह स्वयं पर निर्भर रहती हैं, शिक्षा महिलाओं को विकास की ओर ले जाती है।

अध्ययन उद्देश्य :-

→ शिक्षित महिलाएं भी परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ।

→ परिवार के सदस्य के बीच संबंधों को मजबूत बनाना।

समाज में भूमिका :-

→ शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करना।

→ सामाजिक कुश्रितियों और उदारवादी विचारों के खिलाफ आवाज उठाना।

→ महिला सशक्तिकरण और अधिकारों की लड़ाई के लिए जागरूक होना।

→ सामुदायिक विकास और सेवा के कार्यों में भागीदारी।

→ आर्थिक विकास रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करना।

→ महिलाएं अपने परिवार और समाज में सरकार के परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। वह अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करती हैं, और समाज में एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती हैं।

महिला शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की भूमिका :-

कोविड-19 महामारी के दौरान सभी शिक्षण संस्थान डिजिटल मोड पर हो गए, और ई-लर्निंग पारंपरिक शिक्षा पद्धति का विकल्प बन गया। पारंपरिक शिक्षा की तुलना में डिजिटल शिक्षा अधिक सुलभ और सस्ती है। ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राएं जो बाहर नहीं जा सकते थे, वे छात्र-छात्राएं एवं महिलाएं अपने घर बैठे ही शिक्षण संस्थानों तक पहुंच सकेंगे, और शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। डिजिटल शिक्षा दूर दराज के क्षेत्र तक आसानी से पहुंच सकेंगी, डिजिटल लर्निंग में अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण शामिल है, जो स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। महिलाओं को ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। शिक्षित महिलाएं अपने परिवार समाज और राष्ट्र में योगदान करने के लिए सशक्त बना रही हैं। भारत सरकार महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकती है। शिक्षा में वृद्धि दूरदराज के क्षेत्र में इंटरनेट तक पहुंच, डिजिटल लर्निंग संसाधन उपलब्ध कराने और वर्तमान समय में सरकार महिलाओं को शिक्षित होने और विभिन्न अवसरों में भाग लेने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। महिलाएं कई चुनौतियों का सामना करने व अपनी लगन से बाधाओं को पार करने से नहीं डरती है। ग्राम समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, चाहे राजनीति हो या खेल या शिक्षा या अर्थव्यवस्था आदि। में महिलाओं की मौजूदगी हर क्षेत्र में योगदान दे सकती हैं, इसीलिए महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की अहम भूमिका है।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में शिक्षा का महत्व :-

सामाजिक विकास :- महिलाओं को शिक्षित करने से उन्हें विभिन्न पारिवारिक एवं सामाजिक कलंको को मिटाने और एक प्रगतिशील समाज विकसित करने में मदद मिल सकती है। एक शिक्षित महिला अपने अधिकारों के बारे में जानती है और वह अपने न्याय के लिए लड़ सकती है। उसे किसी पर निर्भर होने या किसी के द्वारा दबाए जाने पर नहीं डरती, वह समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अधिक सशक्त होगी। जैसे चुनाव लड़ना अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज करना आदि।

लैंगिक समानता :- जो महिलाएं शिक्षित हैं, वे महिलाएं अपने परिवार में जागरूकता को बढ़ावा देती हैं। लड़की और लड़कों में भेद भाव नहीं करती हैं, और शिक्षा का सामान अवसर प्राप्त होता है, और वह समाज राष्ट्र, कल्याण को बढ़ाने का योगदान करने में मदद करते हैं। शिक्षा समाज में पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी को बनाए रखने का समर्थन करती है।

आर्थिक विकास :- शिक्षित महिलाएं परिवार, समाज, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षित और कुशल महिला का कार्यबल विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होंगी। इससे अंततः देश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और समृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा।

बेहतर जीवन स्तर :- जैसे-जैसे महिलाएं शिक्षित और कुशल होंगी वे विभिन्न पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, गतिविधियों में शामिल होंगी। शिक्षा से महिलाओं में विकास को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, और वे अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकती हैं।

परिवार एवं बच्चे की स्वास्थ्य में देखभाल :- सभी समाज के लिए स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पोषण की आवश्यकता परिवार के अन्य सदस्यों में समान होती है। इसकी आवश्यक मात्रा उम्र, वजन, लंबाई, और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार अलग-अलग होती है। बच्चों के विकास एवं वृद्धि के लिए ऊर्जा की मांग अधिक होती है, शिक्षित एवं जागरूक महिला अपने परिवार के साथ-साथ पोषण के प्रति समुदाय को भी जागरूक करेंगी, और सरकार द्वारा चलाई गई योजना का भी लाभ उठा सकेंगी। द स्टेट ऑफ़ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2019 के अनुसार दुनिया में 5 साल से कम उम्र का हर तीसरा बच्चा या दूसरे शब्दों में 70 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को जागरूक करना होगा, कि सिर्फ बच्चों का पेट भरना नहीं, बल्कि उन्हें संतुलित और पोषित आहार देना चाहिए, जो न केवल राष्ट्र की जिम्मेदारी है, बल्कि परिवार को भी अपनी भूमिका समझनी होगी।

शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी :- शिक्षित महिलाएं अच्छी तरह से स्वास्थ्य की देखभाल एवं प्राथमिक उपचारों के बारे में अधिक जानकारी रखती हैं। गर्भावस्था से लेकर शिशु जन्म तक डॉक्टर की देखरेख में अपना प्रसव अस्पताल में ही करवाती हैं। इसीलिए बच्चों में मृत्यु की संभावना कम होती है।

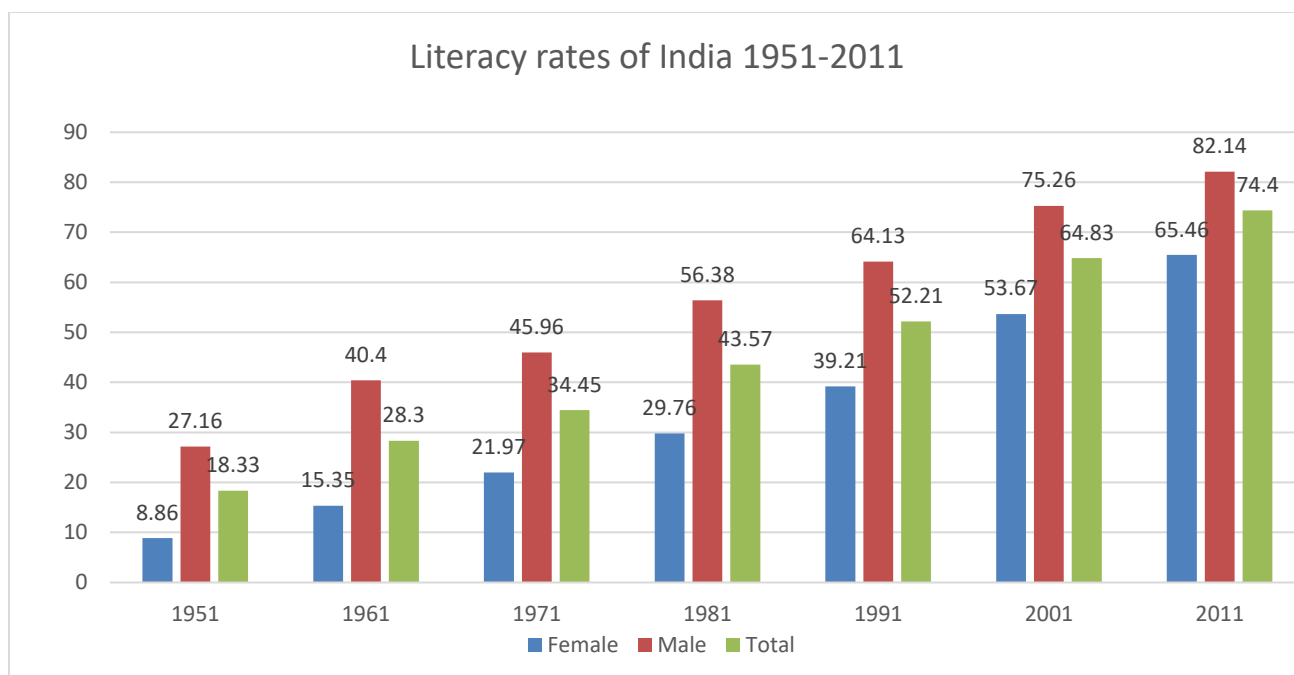
अध्ययन क्षेत्र एवं प्रविधि :- मैंने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गौर ब्लाक में 3 से 6 वर्ष के बच्चों की मां का डाटा साक्षात्कार, प्रश्नावली, सर्वे एवं पत्र पत्रिकाओं विधि से एकत्र किया।

परिणाम:- प्रस्तुत अध्ययन में 200 परिवारों का चयन किया, जिसमें परिवार का स्वरूप और महिलाओं का शैक्षिक स्तर प्राथमिक एवं द्वितीयक विधि द्वारा संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए गए हैं। आंकड़ों का विश्लेषण व्याख्या कर प्राप्त किया गया।

तालिका नं०:-01

स्वतन्त्रता के पश्चात महिलाओं की साक्षरता-दर 1951-2011 :-

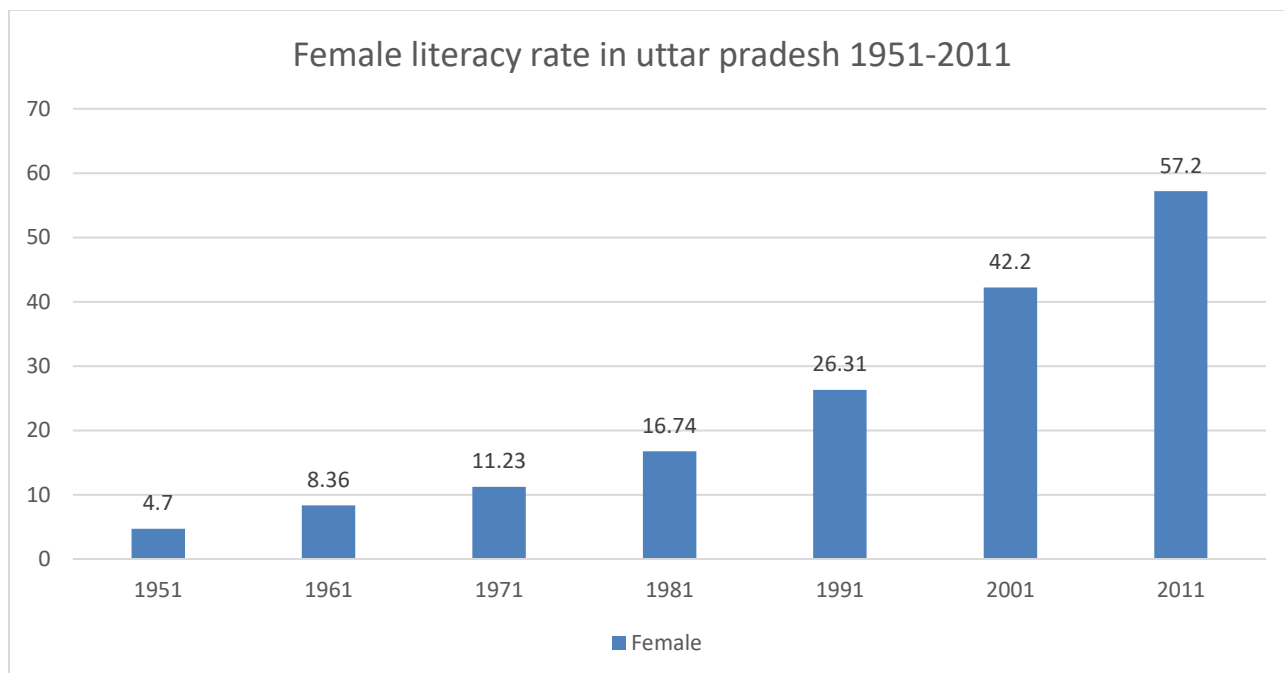
वर्ष	व्यक्ति	स्त्रियाँ	पुरुष
1951	18.33	8.86	27.16
1961	28.30	15.35	40.40
1971	24.45	21.91	45.96
1981	43.47	29.76	56.38
1991	52.21	39.29	64.13
2001	64.38	54.10	75.85
2011	74.04	65.46	82.14



वर्ष 1951–2011 तक शिक्षा में काफी बढ़ोत्तरी हुयी है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय स्त्रियों की शिक्षा तथा रोजगार की ओर उनकी समस्याओं का समाधान का विशेष ध्यान दिया गया। जिसमे शिक्षा के प्रसार से उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायता मिली है। शिक्षा से सभी नारियों को पुरुषों के बराबर समान अधिकार प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में हर क्षेत्र में महिलाएं भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।

तालिका नं०-02

उत्तर प्रदेश मे महिलाओं का साक्षरता दर प्रतिषत में 1951–2011 :-



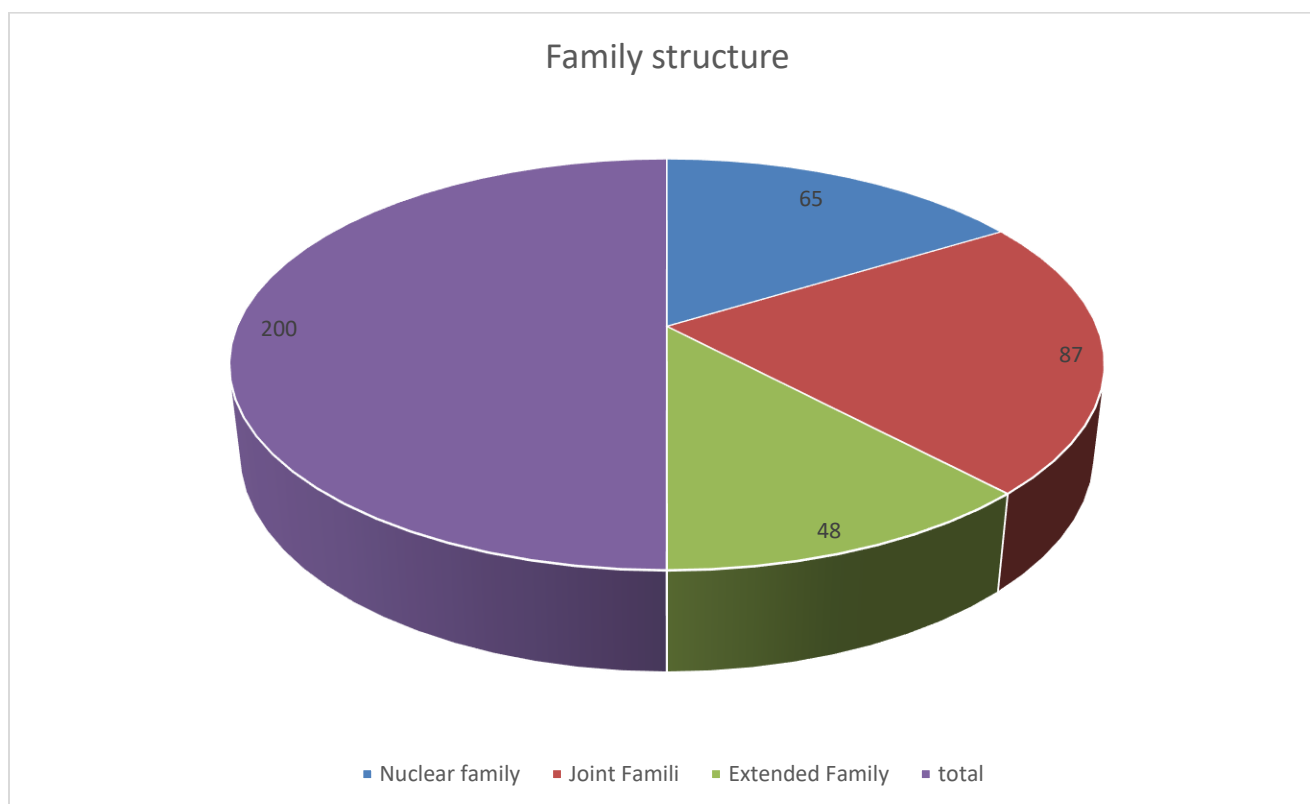
वर्ष 1951 मे उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 12 प्रतिषत थी, यानी 100 प्रतिषत में 88 प्रतिषत लोग अशिक्षित थे। महिलाओं में साक्षरता की स्थिति तो और खराब थी 100 प्रतिषत मे केवल 4 प्रतिषत महिलाएं ही पढ़ी लिखी थी। वक्त के साथ-साथ चीज

बदलती गई और साक्षरता दर बढ़ता गया 1991–2011 तक महिलाओं का शैक्षिक दर 57 प्रतिशत हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साक्षरता दर का लक्ष्य 100 प्रतिशत रखा गया है जो सरकार महिलाओं को शिक्षित एवं रोजगार के लिए प्रेरित कर रही है।

तलिका नं०-3

परिवार का स्वरूप प्रतिशत मे:-

क्रम सं०	परिवार का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
01	एकल परिवार	65	35.5
02	संयुक्त परिवार	87	43.5
03	विस्तारित परिवार	48	24.00
	कुल	200	100%



ग्रामीण क्षेत्र में 200 परिवार का अध्ययन कर डाटा एकत्रित किया गया जिसमें 35.5: घर ऐसे पाया गया जो एकल परिवार में रहते हैं और 43.5: परिवार जो संयुक्त परिवार में रहते हैं और 24: ऐसे हैं जो विस्तारित परिवार से संबंध रखते हैं।



अध्ययन निष्कर्ष:-

जिस प्रकार व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगर महिला शिक्षित नहीं होगी, तो न वे सफल गृहणी बन सकेगी और न ही कुशल माता। एक शिक्षित महिला भविष्य में निराशा एवं शोषण के अंधकार से निकलकर परिवार को सही दिशा दिखा सकती है। शोध निष्कर्ष में पाया कि जिन घरों की मां शिक्षित थी, उनके घरों के बच्चे और विशेष रूप लड़कियों के स्कूल जाने की संभावना अधिक थी, और जिन घरों में परिवार अशिक्षित थे, वहां वयस्क साक्षरता कार्यक्रम आप्रत्यक्ष रूप से माता को शिक्षा का मूल्य सीखने में मदद कर सकते हैं, और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षित पिता की तुलना में शिक्षित मां होने से बच्चों के लिए कई लाभ हैं, जैसे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत, स्वच्छता, पर्यावरण, आर्थिक स्थिति आदि का प्रभाव पड़ता है, और कुछ मामले ऐसे हैं, जिनमें महिलाओं की शिक्षा का विकास पर कम प्रभाव पड़ता है, जैसे नशाखोरी, कन्या भ्रूण हत्या, बच्चों में कुपोषण, गरीबी, जनसंख्या, लिंगीय भेदभाव, आदि। ग्रामीण क्षेत्र में पाया है की बेटियों की शिक्षा के तुलना में बेटों के शिक्षा में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- वाजपेई, हेमा .(2023),ग्रामीण भारत की रूपरेखा बदलती ग्रामीण महिलाएं।
- कौर, मलकीत. शर्मा,एम एल . (1991),ग्रामीण अध्ययन।
- वाजपेई,शालिनी.(2023),भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति।
- के ,आदित्य.(2020), भारत में ग्रामीण विकास महिलाओं की भूमिका।
- यादव सिंह,डॉ निर्मल.(2019), ग्रामीण महिलाओं पर आधुनिकरण का प्रभाव।
- गांधी, महात्मा .(1930) ,यंग इंडिया पत्रिका।
- साधना, प्रीति.(2021), महिला संविधान में शिक्षा की भूमिका. इंटरनेशनल जर्नल।
- तिवारी देवेश, साहू राजेश.(2023) , दैनिक भास्कर <https://share.google>
- सिंह स्वदेश.(2024), सुधारो का एक दशक : शिक्षा और कौशल विकास।